f. Request for additional allotment of kerosene: Government of India has been requested to allot additional 20,000 KL of kerosene per month to meet the requirements of additional BPL cardholders.

g. Request to instruct the oil companies to implement 'Delivered Supply Scheme' *w.e.f.*, 1.1.97, delivered supply of the PDS kerosene.

h. Request for reduction of security deposit under the Deepam Scheme. The State Government has about 28 lakh LPG connections. The security deposit of Rs. 750/- has been paid by the Government to the oil companies on behalf of the beneficiaries, but it has been raised, now, to Rs. 950/- per conncetion *w.e.f.* 09.01.05.

As these proposals are pending for long, I urge upon the Government to kindly expedite approvals for these proposals.

Demand for conservation of Forests along with afforestation

श्री पी.के. माहेश्वरी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, देश में जल व जमीन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं सहित पर्यावरणीय असंतुलन की जड़ें भी जंगलों से ही जुड़ी हुई हैं। दिनों दिन जंगलों व वृक्षों की संख्या में आ रही कमी के कारण जहां एक ओर प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से भयावह रूप लेता जा रहा है वहीं दूसरी ओर भूजल का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है साथ ही मानव सहित सभी जड़ चेतन प्राणियों का जीवन लगातार दूभर होता जा रहा है। इसके बावजूद चिन्ताजनक तथ्य यह है कि सरकार जंगलों की ओर उतना ध्यान नहीं दे रही है, जितना कि दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील है कि अधिक से अधिक तादाद में वृक्षारोपण कराया जाए और इसके लिए सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके मुताबिक आगामी दस वर्षों में देश के 25 फीसदी भू-भाग को वनाच्छादित कर दिए जाने की बात कही गई है। लेकिन सरकार के इस लक्ष्य की प्राप्ति की राह काफी मुश्किल दीख रही है। खास तौर से जिस तेजी के साथ पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे काफी जटिलताएं सामने आ रही हैं। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि सरकारी रिकार्ड में जंगल के रूप में दर्ज कई भूखंडों को बिल्कुल नंगा कर दिया गया है और वहां से पेड़ ही नहीं बल्कि झाड़-झंखाड़ भी पूरी तरह साफ हो गए हैं। साथ ही सड़कों कि किनारे लगवाए गए पेड़ भी काफी बड़ी तादाद में काटे जा रहे हैं। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण के साथ ही अगर वृक्षों के संरक्षण की ओर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो तमाम सरकारी कोशिशों का नतीजा शून्य ही निकलेगा।

Need for evolving resettlement/rehabilitation package for Gold/ Silver Artisan Community in the country

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, an

1495RS—14A